हिन्दी साप्ताहिक

Title Code:- UTTBIL00534

उत्तराखण्ड अभ्युदय

♦वर्ष -01 ♦ अंक-18 ♦देहरादून - रविवार 23 फरवरी 2025 ♦पृष्ठ : 4 ♦मूल्य: 1/-

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को सदन में किया गया याद

देहरादून। विधानसभा सत्र शुरू होते ही सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व प्रधानमंत्री स्व. डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ज्वालापुर के पूर्व विधायक स्व. चंद्रशेखर भट्टे वाले को भी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वह जो प्रेरणा समाज को देकर गए निश्चित रूप से लोग उससे आगे बढ़ेंगे। जितने वो साधारण थे उतना ही उनका असाधारण व्यक्तित्व भी था। उनका योगदान बहुत बड़ा है। उनका निधन सबके लिए अपूरणीय क्षति है।

विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन परिचय हम सबको दिशा देने वाला है। हमने ऐसा व्यक्तित्व खोया है जिसकी देश को आवश्यकता थी। उन्होंने पूर्व विधायक चंद्रशेखर भट्टे वाले को भी याद किया। विधायक मोहम्मद शहजाद ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे देश को बहुत आर्थिक ऊंचाई पर ले गए हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने पूर्व विधायक स्व. चंद्रशेखर को भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। पूर्व विधायक को अंत्येष्टि में जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और भट्टे वाले जी को जन्नत में मुकाम मिले।

मंत्री सतपाल महाराज ने पूर्व पीएम स्व. डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल ऐतिहासिक माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं। सरलता और गंभीरता की प्रतिमूर्ति थे। देश को उन्होंने ऊँचाई पर ले जाने की दिशा में जो काम किया, उसकी छाप आज भी भारत की आर्थिक व्यवस्था में नजर आता है। वर्ष 1987 में उन्हें पद्मविभूषण की उपाधि से सुशोभित किया गया।

देहरादून और हल्द्वानी के स्टेडियम के पूरे नाम न लिखने पर विपक्ष के विधायक सुमित हृदयेश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दो पूर्व प्रधानमंत्री का पूरा नाम निमंत्रण पत्र पर सम्मान से लिखने के बजाय सरकार ने शार्ट में क्यों लिखा। इस पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उनका नाम लिखा गया है, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में 168 आंगनबाड़ी कम क्रेच केंद्रों को स्वीकृति मिली है। अभी बजट का इंतजार। कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 साल तक के बच्चे इन क्रेच(पालन) में रख सकते हैं।

सदन में राशन कार्ड को लेकर सत्तापक्ष के विधायकों ने भी सवाल किए। नए राशन कार्ड बनने पुराने की समीक्षा पर सवाल किए गए। मंत्री ने कहा, राशन कार्डों की समीक्षा को लेकर अभियान चलाए जाते हैं। रिक्ति के सापेक्ष ही नए राशन कार्ड बन सकते हैं।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में 1,76,000, अंत्योदय कार्ड की डिमांड है। कहा कि अगर कोई लगता है कि राशन कार्ड अपात्र की श्रेणी में आ गया है तो इसकी सूचना विभाग या सीएम पोर्टल पर दे सकते हैं।

उत्तराखंड में बाहर वाले नहीं खरीद पाएंगे जमीन

देहरादून। नए भू कानून में उत्तराखंड से बाहर के दूसरे राज्य के लोगों के लिए कृषि, उद्यान की जमीन खरीद को प्रतिबंधित कर दिया है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़ शेष 11 जिलों में दूसरे राज्य के लोग कृषि, उद्यान की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सिर्फ हरिद्वार और उधमसिंह नगर में ही बाहर वाले कृषि, उद्यान के लिए जमीन खरीद सकेंगे।

पहाड़ों पर बाहर के लोगों के तेजी से जमीन खरीदने से तेजी से होते डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने को जमीन खरीद प्रक्रिया पर शिकंजा कस दिया गया है। अभी तक उत्तराखंड में बाहर के लोग बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर और मंजूरी लेकर साढ़े 12 एकड़ से भी अधिक जमीन कृषि, उद्यान के लिए खरीद सकते थे। इससे पहाड़ के पहाड़ बाहर के लोगों ने वर्ष 2018 के बाद से खरीदे। इससे पहाड़ पर बाहर के लोगों का मूवमेंट तेजी से बढ़ा। बाहरी लोगों के इसी बढ़ते दबाव में सख्त भू कानून की मांग उठी। बुधवार को धामी कैबिनेट ने बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।

कैबिनेट ने हरिद्वार और उधमसिंहनगर को इस प्रतिबंध से मुक्त रख कर पहाड़ मैदान को भी साधने का काम किया। 11 जिलों में सख्त भू कानून की मांग की जा रही थी, तो हरिद्वार, यूएसनगर में भूकानून को थोड़ा नरम रखने की मांग की जा रही थी। सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए प्रतिबंध को 11 पहाड़ी जिलों तक सीमित रख दिया है।

जिलाधिकारियों का अधिकार किया समाप्त: बाहरी लोगों को अभी तक जिलाधिकारी स्तर से जमीन खरीद की आसानी से मंजूरी मिल रही थी। इस व्यवस्था को भी कैबिनेट ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब जिलाधिकारी स्तर से मंजूरी देने के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया है। अब कृषि, उद्यान को छोड़ कर अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी को जमीन खरीदनी होगी, तो मंजूरी जिलाधिकारी नहीं देंगे। बल्कि प्रस्ताव शासन को भेजना होगा। शासन स्तर से ही उस पर निर्णय लिया जाएगा।

राज्य की जनता की लंबे समय से चली आ रही सख्त भू कानून की मांग को पूरा किया गया है। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

उत्तराखंड की जमीनों पर बाहरी लोगों के लैंड बैंक को भाजपा जिम्मेदार: दसौनी

देहरादून। कांग्रेस प्रदेश की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की जमीनों पर बाहरी लोगों के लैंड बैंक के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या पूर्व में नियमों के विपरीत खरीदी गई जमीनों को क्या सरकार मुक्त कराएगी? मीडिया को जारी बयान में दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग लंबे से चली आ रही है। कहा कि धामी सरकार का भू कानून कितना सख्त और कितना नरम है यह तो बाद में ही पता चलेगा लेकिन राज्य की जमीनों की बंदरबांट के लिए पूरी तरह से भाजपा सरकारें ही दोषी हैं। कहा कि पहले तो भाजपा सरकार यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं कर पाई। अभी तक भी उत्तराखंड की अरबों की संपत्ति यूपी के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी और बीसी खंडूड़ी सरकार में भूमि की खरीद फरोख्त पर सख्त नियम बनाए गए थे, परंतु 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पूरी तरह से उत्तराखंड की भूमि बाहरी लोगों के लिए खरीद-फरोख्त का रास्ता खोल दिया। गरिमा ने कहा कि पूर्व वर्ती सरकारों में यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति खरीदी हुई भूमि पर दो साल के अंदर जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली गई है ।

कांग्रेस विधायकों ने किया स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने पर विरोध प्रदर्शन

देहरादून। उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य विधानसभा के सदस्य यशपाल आर्या ने कहा कि आज हम लोग स्मार्ट मीटर को लेकर, जो इस राज्य में सरकार लागू करना चाहती है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस अन्य मुद्दों को भी सदन में लाना चाहता हूं। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा...

यशपाल आर्या ने कहा कि सरकार अहंकार में डूब चुकी है और सत्र की अवधि को बढ़ाना नहीं चाहती है। हमारे प्रमुख जन मुद्दों से सरकार चर्चा कराने से बचना चाहती है, क्योंकि सरकार डरी हुई है। चारो तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज हम प्रीपेड मीटर को लेकर जो सरकार इस राज्य में लागू करना चाहती है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अन्य मुद्दों को भी सदन में लाना चाहती है, जैसे सशक्त भू कानून, पलायन, रोजगार, आपदा आदि।

बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कई तरह की तख्तियां हाथों में लिए पाए गए। इनमें कई तरह के नारे लिखे थे, जिनमें स्मार्ट मीटर के विरोध से जुड़े भी थे। महिला सदस्य के हाथ की तख्ती में लिखा था, ये स्मार्ट मीटर नहीं चीटर है। इसके साथ ही सत्र की अवधि को बढ़ाने जैसी मांग भी लिखी थी। कानून और मूल निवास का हक दिलाने की मांग भी की गई थी। वहीं तख्ती के जरिए आरोप लगाया गया था भाजपा जनता की आवाज दबा रही है।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस कड़ी में खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में शव यात्रा भी निकाली थी और बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर जाकर भी प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों ने प्रीपेड मीटर को जन विरोधी करार दिया था। इसके साथ ही सरकार से इस प्रक्रिया को तत्काल बंद करने की मांग की थी। इसीके चलते विधानसभा सत्र में भी किए गए प्रदर्शन में बिजली मीटर का मुद्दा गरमाया रहा।

सम्पादकीय

विकसित उत्तराखण्ड हेतु सशक्त संकल्प

हिमगिरौ निर्जिता गङ्गा यमुनायाश्च उद्गमे।
तिष्ठत्ययं तपोभूमि: देवभूमिर्विराजते
शौर्येण वीरभूमि: सा पर्वतानां सदा विभा।
खेलभूमिर्यशोवृद्ध्या कीर्तिं लभत भारतम्

अर्थात्

हिमालय के शिखरों पर जहां से गंगा और यमुना का उद्गम होता है, वहाँ स्थित यह उत्तराखंड तपोभूमि एवं देवभूमि के रूप में सुशोभित है।

यहां रहने वाले व्यक्तियों के पराक्रम और शौर्य के कारण यह भूमि, वीरभूमि कहलाती है। वर्तमान में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर यह खेलभूमि बन कर भारत के गौरव को बढ़ा रही है।

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। नमो बजट को नवाचार,आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन के जरिये परिभाषित किया गया है।नवाचार में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रणामीकरण, ऊर्जा दक्ष पंप, स्मार्ट मीटर, विज्ञान केंद्र, साइंस सिटी आदि का जिक्र किया गया है।सरकार आत्मनिर्भर उत्तराखंड के तहत कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग और अवसंरचना, पर्यटन पर फोकस करेगी। ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। महान विरासत के तौर पर सरकार शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन की सुगमता, हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास और शारदा रिवर फ्रंट की योजनाओं पर काम करेगी। मानव संसाधन के तौर पर सरकार उद्यमिता, स्टार्ट अप, नॉलेज इकॉनोमी, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), खेल सुविधाएं, खिलाडिय्यों और किसानों को प्रोत्साहित करने का काम करेगी। उन्होंने ज्ञान मंत्र का जिक्र किया कि बजट में सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी कल्याण को केंद्र में रखा है। बजट में जो नई योजनाएं लेकर आए हैं, उनमें वेंचर फंड बनाने, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, प्रवासी उत्तराखंड परिषद, यूआईटीडीबी को परामर्शी सेवाओं व सर्विस सेक्टर सब्सिडी, रेणुका जी बांध परियोजना में राज्य की अंशपूंजी, खेल विवि की स्थापना, होम कल्याण कोष, सैनिक विश्राम गृहों की साज सज्जा प्रमुख हैं। यह सुखद है कि देवभूमि, तपोभूमि, वीरभूमि अब खेलभूमि होने की ओर अग्रसर है।

जय देवभूमि उत्तराखण्ड!! जय भारत!!

डॉ.गार्गी मिश्रा

गर्मी ने न हिमाचल प्रदेश की सुरम्य वादियों को बख्शा, न उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को

पंकज चतुर्वेदी

लोगों के तन से होली के रंग छूटे भी नहीं थे कि पूरा उत्तरी भारत तीखी गर्मी की चपेट में आ गया था। कुछ जगह पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात भी हुई, पर ताप कम नहीं हुआ। देश के लगभग 60 फीसदी हिस्से में अब 35 से 45 डिग्री की गर्मी के कहर के 100 दिन हो गये हैं और चेतावनी है कि अगले दो हफ्ते मौसम ऐसा ही रहेगा। वैसे भी यदि मानसून आ भी गया, तो भले तापमान नीचे आये, लेकिन उमस गर्मी की ही तरह तंग करती रहेगी।

चिंता की बात है कि इस बार गर्मी के प्रकोप ने न तो हिमाचल प्रदेश की सुरम्य वादियों को बख्शा और न ही उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को। गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की तरह तीखी गर्मी की चपेट में आ रहा है। यहां पेड़ों की पत्तियों में नमी के आकलन से पता चलता है कि आगामी दशकों में हरित प्रदेश कहलाने वाला इलाका बुंदेलखंड की तरह सूखे, पलायन व निर्वनीकरण का शिकार हो सकता है। आधा जून बीत गया, पर अभी भी शिमला और मनाली जैसे स्थानों का तापमान 30 के आसपास है। हमीरपुर में 44। 5, तो कांगड़ा, चंबा, नाहन,मंडी आदि में पारा 41 से नीचे आने को तैयार नहीं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 122 साल बाद सबसे ज्य्यादा तापमान 42। 4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा पंतनगर का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा। मुक्तेश्वर और टिहरी में ऐसी ही स्थिति है। यह समझना होगा कि मौसम के बदलते मिजाज को जानलेवा हद तक ले जाने वाली हरकतें तो इंसान ने ही की हैं। प्रकृति की किसी भी समस्या का निदान हमारे अतीत के ज्ञान में ही है, कोई भी आधुनिक विज्ञान ऐसी दिक्कतों का हल नहीं खोज सकता। आधुनिक ज्ञान के पास तात्कालिक निदान और कथित सुख के साधन तो हैं, लेकिन कुपित कायनात से जूझने में वह असहाय है।

यह गर्मी अब इंसान के लिए संकट बन रही है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में इसने हवा की गुणवत्ता को खराब किया है। इसके अलावा लू लगने, चक्कर आने, रक्तचाप अनियमित होने से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। लगातार गर्मी ने पानी की मांग बढ़ायी है और संकट भी। पानी का तापमान बढ़ना तालाब-नदियों की सेहत खराब कर रहा है। एक तो वाष्पीकरण तेज हो रहा है, दूसरा पानी अधिक गरम होने से जलीय जीव-जंतु और वनस्पति मर रहे हैं। तीखी गर्मी भोजन की पौष्टिकता की भी दुश्मन है।गेंहू, चने के दाने छोटे हो रहे हैं और उनके पौष्टिक गुण घट रहे हैं। तीखी गर्मी में पका हुआ खाना जल्दी सड़ रहा है, फल-सब्जियां जल्दी खराब हो रही हैं। केमिकल लगा कर पकाये गये फल इतने उच्च तापमान में जहर बन रहे हैं। इस बार एक त्रासदी यह है कि रात का ता. पमान कम नहीं हो रहा, चाहे पहाड़ हो या मैदानी महानगर, बीते दो महीनों से न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक अधिक रहा है। सुबह चार बजे भी लू का एहसास होता है और इसका कुप्रभाव यह है कि बड़ी आबादी की नींद पूरी नहीं हो पा रही। इससे लोगों की कार्य क्षमता पर तो असर हो ही रहा है, शरीर में भी कई विकार बढ़ रहे हैं।

जो लोग सोचते हैं कि वातानुकूलित संयंत्र से वे गर्मी की मार से सुरक्षित है, तो यह भ्रम है। लंबे समय तक एयर कंडीशनर वाले कमरों में रहने से शरीर की नस-नाड़ियों में संकुचन, मधुमेह और जोड़ों के दर्द का खामियाजा जिंदगी भर भोगना पड़ सकता है। इस साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भारत में एक लाख लोगों का सर्वे कर बताया है कि गर्मी/लू के कारण गरीब परिवारों को अमीरों की तुलना में पांच फीसदी अधिक आर्थिक नुकसान होगा। चूंकि आर्थिक रूप से संपन्न लोग बढ़ते तापमान के अनुरूप अपने कार्य को ढाल लेते हैं, पर गरीब ऐसा नहीं कर पाते। भारत के बड़े हिस्से में दूरस्थ अंचल तक 100 दिन के विस्तार में लगातार बढ़ता तापमान न केवल पर्यावरणीय संकट है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक त्रासदी तथा असमानता और संकट का कारक भी बन रहा है। सवाल यह है कि प्रकृति के इस बदलते रूप के सामने इंसान क्या करे? यह समझना होगा कि मौसम के बदलते मिजाज को जानलेवा हद तक ले जाने वाली हरकतें तो इंसान ने ही की है। प्रकृति की किसी भी समस्या का निदान हमारे अतीत के ज्ञान में ही है, कोई भी आधुनिक विज्ञान ऐसी दिक्कतों का हल नहीं खोज सकता। आधुनिक ज्ञान के पास तात्कालिक निदान और कथित सुख के साधन तो हैं, लेकिन कुपित कायनात से जूझने में वह असहाय है।

जी-7 में भरोसेमंद आवाज बन गया है भारत

अनिल त्रिगुणायत

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मेजबानी में 13 से 15 जून तक हुआ जी-7 शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ, जब अहम बदलावों से गुजर रही दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। इनमें यूरोप और मध्य-पूर्व में जारी दो युद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो जी-7 देशों- अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान- की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उदारवादी व्यवस्था बड़े दबाव में हैं, जिसके लगभग पतन के लिए इसके संस्थापक एवं समर्थक भी समान रूप से जवाबदेह हैं। बहुपक्षीय व्यवस्था एवं संस्थाओं को अनसुना कर ये देश एकतरफा फैसले लेते रहे हैं, मनमाने ढंग से आर्थिक एवं वित्तीय पाबंदियां लगायी जाती रही हैं तथा ऐसे उपाय किये जाते रहे, जिनका अनुपालन ये देश स्वयं भी नहीं करते हैं। यह कहा जाना चाहिए कि नये विकल्प के बीज बहुत हद तक इनके द्वारा ही बोये गये हैं। जी-7 की स्थापना 1975 में की गयी थी, जब 1973 के अरब-इस्राइल युद्ध और उसमें अमेरिका की भूमिका की वजह से अरबों ने तेल की आपूर्ति रोक दी थी और सामुद्रिक आवाजाही बाधित हुई थी, जिसके कारण बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भारी झटका लगा था। पांच दशकों के बाद 50वीं बैठक के सामने भी कुछ उसी तरह की चुनौतियां रहीं, जो कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा इस्राइल-हमास संघर्ष के कारण पैदा हुई हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध तथा इस्राइल-हमास संघर्ष बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकते हैं, जिनकी चपेट में आकर समूची दुनिया झुलस सकती है। परमाणु तबाही के बारे में बात करना आम चलन बन गया है तथा नये-नये घातक एवं स्वायत्त हथियारों को सामने लाया जा रहा है। साथ ही, चीन आज जी-7 समूह के लिए एक अस्तित्वगत चुनौती बन चुका है। चीन के प्रभाव को रोकने की कोशिश में समूह द्वारा जो तौर-तरीके और उपाय अपनाये जा रहे हैं, उनके कारण रूस और चीन के बीच नजदीकी बढ़ती जा रही है, जो पश्चिम के वर्चस्वादी व्यवहार का प्रतिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों देश अपने तरीके से एक नयी विश्व व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रमुखता के बारे में कहा जा रहा है। ऐसा विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है, जो खुद ही लाचार और बेहाल हो चुका है।

लेकिन इस वैकल्पिक व्यवस्था में ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और यूरेशिया क्षेत्र पर जोर देना एक वास्तविकता है। वर्तमान समय में जी-7 का पूरा ध्यान यूक्रेन में रूस के आक्रमण तथा अप्रत्यक्ष युद्ध से पुतिन को हराने पर है ताकि यह समूह अपने को बिखर रहे नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बचाने वाले के रूप में स्थापित कर सके। शिखर बैठक के मुख्य अतिथि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उन्नत हथियार देने का प्रावधान तथा जब्त रूस की संपत्ति में से 50 अरब डॉलर यूक्रेन को देने पर सहमति से पुनः राष्ट्रपति चुने गये पुतिन और भी अधिक आक्रामक होंगे। जब तक पश्चिम इस युद्ध में यूक्रेन को सहयोग करता रहेगा, स्थिति में बदलाव नहीं हो सकता है। गलती से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोल गये कि आखिरी यूक्रेनी व्यक्ति के बचे रहने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।

भू-राजनीतिक रूप से विभाजित शीत युद्ध के दूसरे संभावित संस्करण में जी-7 समूह एक खेमे के रूप में उभरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भू-आर्थिक दृष्टि से नयी विश्व व्यवस्था में आर्थिक शक्ति के अनेक केंद्र होंगे। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि पलड़ा पूर्व और दक्षिण की ओर झुका है, जिसमें भारत न केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, बल्कि पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण के बीच पुल निर्माता एवं ग्लोबल साउथ की एक भरोसेमंद आवाज के रूप में भी एक ठोस भूमिका निभायेगा। सिद्धांत आधारित विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता से भारत की शक्ति बढ़ी है, जिसमें 'भारत प्रथम' की सोच के साथ विश्व की भलाई एवं कल्याण की भावना प्रमुख तत्व है। उलझी-बिखरी व्यवस्था में इसकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, पर आशा का एक दीप बनने की नैतिक क्षमता भारत में है।

भारत एक तरह से जी-7 का अभिन्न अंग बन चुका है। इसे 11 बार सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पांच बार इसमें शामिल हो चुके हैं तथा उन्होंने प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त कर बैठकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका इटली दौरा पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के कार्यकाल में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा दोनों देशों के हितों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इस्राइल-हमास संघर्ष की वजह से अभी इस मामले में प्रगति बाधित हुई है। उल्लेखनीय है कि अफ्रीका, भू-मध्यसागर के क्षेत्र तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी जी-7 और भारत के बीच सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा नियमन, जलवायु परिवर्तन तथा उन्नत तकनीक से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। समूची मानवता के फायदे के लिए इनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इन तकनीकों का गलत इस्तेमाल न हो, इसके लिए भी साझा प्रयासों की जरूरत है। इन कारणों से वैश्विक सहकार बहुत अहम हो जाता है, लेकिन बड़ी शक्तियों की आपसी खींचतान और तनातनी से ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत एक संपर्क-सूत्र की भूमिका निभा सकता है। भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता, सार्वभौमिक कल्याण और चिंताओं का प्रदर्शन जी-20 की अध्यक्षता के दौरान बखूबी किया है, जिससे यह इंगित हुआ कि भारत दुनिया की भलाई के लिए सभी को साथ लेकर चलने का आकांक्षी है। सकल घरेलू उत्पादन के मामले में जी-7 समूह की चार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भारत आगे निकल चुका है। इसके निरंतर विकास और विश्व में बड़ी भूमिका की कोशिश से वह अपने सिद्धांत-आधारित विदेश नीति को आगे बढ़ाने की स्थिति में है।

कठिन नहीं रोचक विषय है गणित

गणित एक ऐसा विषय है, जिसमें सही उत्तर दिए जाने पर पूरे अंक मिलते हैं। इस तरह यह अंक बटोरने का सबसे उपयोगी विषय बन जाता है। गणित के बारे में 'कठिन विषय' जैसी भ्रांतियों से इतर कुछ बुनियादी योजनाएं बना कर इसकी तैयारी आसानी से की जा सकती है।

कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि गणित कठिनतम विषयों में से एक है, किंतु यह एक भ्रांति मात्र है।

यदि सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से नियमित रूप से लिखित अभ्यास किया जाए तो यह विषय आपको अप्रत्याशित सफलता प्रदान करेगा। समय का उचित प्रबंधन एवं सदुपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विषय लिखित अभ्यास के अभाव में अपूर्ण है। प्रायः देखा गया है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को विज्ञान के छात्रों की अपेक्षा गणित अधिक कठिन लगता है एवं वे गणित को रटने की कोशिश करते हैं। गणित रटने का नहीं, बल्कि समझने का विषय है।

यदि समझ कर प्रश्नों को हल किया जाए तो न केवल उन्हें हल करना आसान हो जाएगा, अपितु विषय भी सरल लगने लगेगा।

हॉट्स (डळर) एवं वैल्यू बेस्ड प्रश्नों का वेटेज 2० अंक है। हॉट्स के लिए विशेषतः उन प्रश्नों पर ध्यान दें, जिनमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हों एवं जो प्रायोगिक (एप्लिकेशन बेस्ड) हों। वैल्यू बेस्ड प्रश्न प्रायः मैट्रिक्स, प्रॉबेबिलिटी एवं एलपीपी से होते हैं एवं जीवन के नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर केवल हां या न में न देकर विश्लेषणात्मक ढंग से नैतिक मूल्यों को ध्यान में रख कर दें।

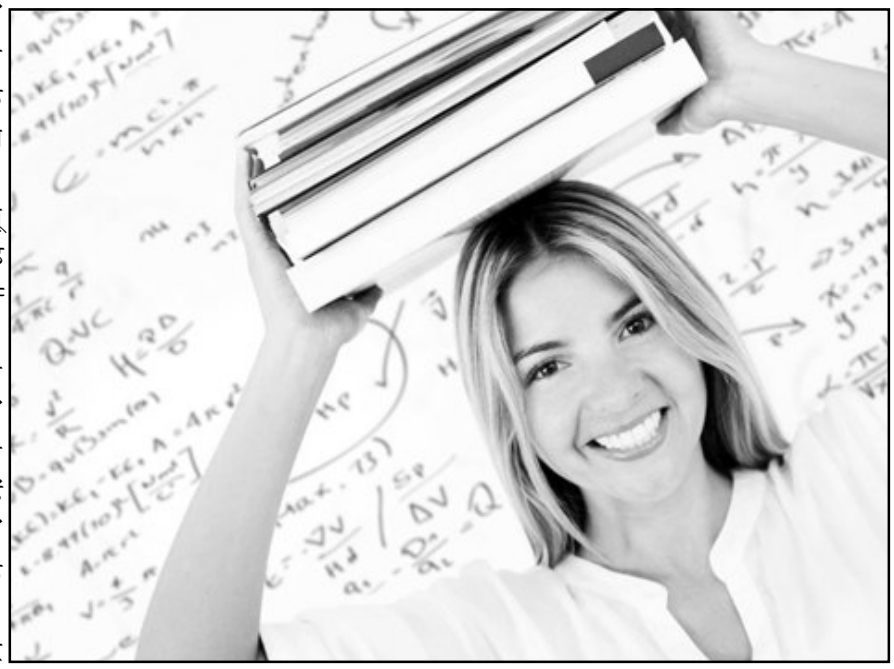

महत्वपूर्ण अध्याय

इंटिग्रेशन, वेक्टर्स एवं 3डी ज्योमेट्री पर विशेष ध्यान दें। इंटिग्रेशन के प्रश्न कॉन्सेप्ट आधारित होते हैं, उदाहरण के लिए स्पेशल इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रेक्शंस, डेफिनिट इंटीग्रल्स इत्यादि, जिन्हें खास तकनीक से हल किया जाता है।

विद्यार्थी हर कॉन्सेप्ट और उनके हल करने की तकनीक का अलग कार्ड बना कर रखें एवं इनका उपयोग रेडी रैकनर की तरह करें। इसी तरह विभिन्न चैप्टर्स के फॉमरूलों का भी कार्ड बना लें तथा उन्हें उपयोग करें।

छह अंक के प्रश्नों के लिए चैप्टर चार में सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर में मैक्सिमा और मिनिमा, चैप्टर 8,9,11,12 एवं 13 में बेयस थ्योरम और रैण्डम डिस्ट्रीब्यूशन पर विशेष ध्यान दें एवं एनसीईआरटी पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें।

विशेष सावधानियां

* स्टेप्स को फॉलों करें। सीबीएसई द्वारा निर्धारित मार्किंग स्टेप्स पर आधारित होती है। प्रश्न हल करते समय उपयोग किए गए फॉर्मूलों को स्पष्ट करें।

* परीक्षा के दौरान हमेशा उन प्रश्नों के उत्तर पहले लिखें, जो आपको भली-भांति आते हों।

प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)

* उत्तर पुस्तिका में साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित ढंग से प्रश्नों के उत्तर लिखें।

* रफ कार्यों को अवश्य दिखाएं।

* डायाग्राम को ग्राफ पेपर पर पेंसिल एवं स्केल की सहायता से बनाएं। उपयोग किए गए फॉमरूले को दर्शाएं। उपयरुक्त सुझावों पर ध्यान देने पर निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी।

विशेष बातें = क्या करें

1. सर्वप्रथम एनसीईआरटी के प्रश्नों को पूर्ण रूप से करें इसके बाद ही किसी रिफ्रेशर का प्रयोग करें।

2. वर्ष 2००8 से 2०13 तक के प्रश्न पत्रों को हल करें।

सीबीएसई सैम्पल पेपर 2००8, 2०1०, 2०12 एवं 2०13 को अवश्य हल करें एवं उनकी मार्किंग स्कीम पर अवश्य ध्यान दें।

3. मॉक परीक्षा अत्यंत आवश्यक है एवं इन्हें ढाई घंटे में हल करें। अपने विद्यालय के शिक्षक से मॉक टैस्ट अधिक से अधिक लेने का आग्रह करें।

4. प्रश्नों की प्रकृति एवं मांग को समझों। प्रश्नों में दिए गए विवरण में ही उनका हल छुपा रहता है, उन्हें समझों एवं प्रश्न की मांग के अनुसार उन्हें हल करें।

क्या न करें

* प्रश्नों के हल को रटे नहीं। जब मानसिक अथवा शारीरिक रूप से आप थके हों तो गणित कभी न करें। गणित का अभ्यास केवल तभी करें, जब आप मानसिक एवं शारीरिक रूप से तरोताजा एवं ऊर्जावान हों।

* गणित को बोझ कभी न समझों, बल्कि इसे समझ कर विषय में रुचि जागृत करें। इससे विषय सरल व सरस लगेगा।

अनोखा मिनी डेस्कटॉप

किसी जमाने में कंप्यूटर कमरे जितने आकार के होते थे। फिर वे घटते-घटते अपने मौजूदा आकार में आ गए, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि पिछले दो-तीन दशक से कंप्यूटर और सीपीयू टावर के आकार में और कमी नहीं आई है। आज का कंप्यूटर सीपीयू आपकी डेस्क पर काफी स्थान लेता है। अगर आप उसे कहीं साथ ले जाना चाहें तो वह भी बहुत मुश्किल है।

उसकी इसी सीमा की वजह से लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट्स लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन पारंपरिक कंप्यूटर ने भी अब बदलने का फैसला कर लिया है और अपने नए रूप में वह लैपटॉप तथा टैबलेट्स के लिए चुनौती सिद्ध हो सकता है। आप पूछेंगे कि कैसे? इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए जरा एसस (अ242) नामक कंपनी का ताजातरीन वीवो पीसी वीसी 6० पर एक नजर डालिए।

एसस वीवो पीसी किसी टिफिन बॉक्स जितने आकार का सीपीयू है, जिसमें कंप्यूटर की तमाम सुविधाएं और क्षमताएं मौजूद हैं। अपने छोटे आकार की वजह से इसे मिनी डेस्कटॉप कहा जा रहा है। आम तौर पर आपने कंप्यूटर के सीपीयू का आकार लंबवत देखा होगा। सात-आठ इंच चौड़ा, सवा फुट ऊंचा और करीब इतना ही लंबा। अगर एक के ऊपर एक रखे जाएं तो ऐसे सीपीयू जितने आकार में कम से कम एक दर्जन वीवो पीसी समा जाएंगे। यह एक वर्गाकार बॉक्स जैसा दिखता है, जिसका आकार किसी एक्सटर्नल डीवीडी ड्राइव जितना ही है। चौड़ाई और लंबाई करीब-करीब एक फाउंटेन पेन जितनी और ऊंचाई महज 5.5 सेंटीमीटर (करीब सवा दो इंच)।

बहरहाल, वीवो पीसी के आकार को देख कर यह न सोच लें कि यह आम कंप्यूटरों से किसी मायने में कम शक्तिशाली है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि छोटे आकार में होने के बावजूद इसमें लगभग वही सब उपकरण मौजूद हैं, जो किसी सामान्य कंप्यूटर के सीपीयू में होते हैं। शक्तिशाली इन्टेल कोर आई3 और कोर आई5 माइक्रोप्रोसेसर से युक्त मिनी डेस्कटॉप में पांच सौ जीबी की सीगेट मोमेन्टस इंटरनल हार्ड डिस्क और चार जीबी रैम मौजूद है। वाई-फाई सुविधा, चार यूएसबी 3.० पोर्ट, एक एसडी कार्ड स्लॉट, एचडीएमआई पोर्ट, मिनी डिस्प्ले पोर्ट, दो यूएसबी 2.० पोर्ट, लैन पोर्ट और ऑडियो तथा माइक्रोफोन जैक भी मौजूद हैं। वायरलैस कीबोर्ड और माउस साथ आते हैं। पूरे सीपीयू का वजन है सिर्फ 12०० ग्राम यानी कहीं भी ले जाने के लिए बहुत सुविधाजनक। वीवो पीसी में विंडोज 8 पहले से इन्स्टॉल किया हुआ आता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उंगलियों की मुद्राओं को पहचानने की क्षमता है, लेकिन सामान्य कंप्यूटरों में हम इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वीवो पीसी के साथ एक खास किस्म का वीवो माउस भी उपलब्ध है, जो एक उंगली, दो उंगली और अनेक उंगलियों के जरिए दिए जाने वाले टैबलेट्स जैसे कमांड्स का इस्तेमाल संभव बनाता है। हालांकि यह माउस अलग से खरीदना पड़ता है।

शरीर को चुस्त-दुरूस्त बनाए रखने के लिए...

सर्दियों के मौसम में अमूमन आलस आना एक कॉमन समस्या बन जाती है।

हर चौथा व्यक्ति कहता है कि सुस्ती लग रही है। थकान सी महसूस हो रही है। दरअसल सर्दियों में दिन छोटा और रात लंबी होने लगती है। देर तक सोने से सोने और जगने के बीच बैलेंस बिगड जाता है। सिर भारी रहने और नींद आने की समस्या बढ जाती है। तमाम लोगों को शाम होते ही सो जाने का मन करता है। तनाव या चिंता हम पर हावी होने लगती है। ये सारे लक्षण किसी नई बीमारी को जन्म दे सकते हैं। ?से में जरूरी है कि इस मौसम में एनर्जी बनाए रखें, सक्रिय रहें तो थकान खुद ब खुद छूमन्तर हो जाएगी।

सूत्रों की जानकारी के अनुसार सर्दियों में प्राकृतिक रोशनी कम मिलती है। इससे ब्रेन में नींद वाला हार्मोन यानी मेलैटोनिन हार्मोन बनने लगता है। इससे शाम होते ही नींद आने लगती है। दूसरे इस मौसम में खाने-पीने की सक्रियता बढ जाती है। बाहर की ?क्टिविटी घट जाती है। ड्रिंक जैसी चीजों की सक्रियता भी बढ जाती है। वेट बढने लगता है और आलस हावी हो जाता है। उस पर से थकान, यह कंडीशन हैल्थ के लिहाज से ठीक नहीं है।

बीमार होने का खतरा ज्यादा रहता है वैसे भी ठंड का मौसम कई तरह की बीमारी ले आता है। इस दौरान वेट बढने, वायरल थायराइड के सही से काम न करने, ह्रदय के रोग होना, शुगर की समस्या, पेट या छाती के संक्रमण, तनाव, चिंता आदि के लक्षण बढ जाते हैं। इनके साथ अगर थकान या आलस जैसी कंडीशन है तो ठीक नहीं है। इससे ये लक्षण बडी बीमारी का रूप ले सकते हैं। बेहतर यही होगा कि का चुस्त शरीर दुरूस्त बनाए रखा जाए, जिससे थकान हावी न होने पाए। बॉडी में एनर्जी कम ना होने दें इस मौसम में एक्सर्साइज जरूरी है। मिनरल की कमी न होने दें। शरीर में पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की बोतल साथ रखें।फल और सब्जी के साथ शरीर की ऊर्जा बनाए रखें। आयरन जिन चीजों में मिले, उन सब्जियों व फलों का सेवन करें। वेट न बढने दें। तनाव आदि को हावी न होने दें। शराब जैसी चीजों से दूर रहें। एनर्जी ड्रिंक आदि परमानेंट साल्यूशन नहीं है, यह थोडी देर के लिए ही एनर्जी दे सकता है। डॉक्टर से पूछ कर ही विटामिन आदि लें।

डायनेस्टी में धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती

रुद्रपुर। डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी छिनकी फॉर्म खटीमा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हुए कार्यक्रम का शुभारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं के गुणगान व उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों ने शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित भावों को कविता, नृत्य आदि के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा दिए गए बलिदान के विषय में विस्तार पूर्वक समझाया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक धीरेंद्र चंद्र भट्ट ने विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब लक्ष्य जीतने का हो तो उसे प्राप्त करने के लिए कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य ,क्यों न हो उसे चुकाना ही पड़ता है।" यह

पंक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित है।"कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य का मार्ग ही आपको साहसी बनाता है। निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य को पूर्ण करें। उन्होंने विद्यार्थियों को शिवाजी महाराज के चरित्र से अनुसरण करने को कहे।

जिले के विकास में सकारात्मक सहयोग करें मीडिया

नई टिहरी। नवनियुक्त जिला सूचना अधिकारी द्रवनीता शर्मा ने पत्रकारों से शिष्टाचार मुलाकात कर जिले के विकास में सहयोग की अपेक्षा की। पत्रकारों से लेकर अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी भजनी भंडारी और सूचना विभाग के कर्मियों ने नवनियुक्त सूचना अधिकारी का स्वागत किया। नव नियुक्त जिला सूचना अधिकारी ने पत्रकारों से परिचय प्राप्त करते हुए विकास के भौगोलिक और समसामयिक जानकारी ली। कहा कि उन्होंने मीडिया कर्मियों से सूचनाओं के आदान-प्रदान और सरकार की नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग करने की अपेक्षा की। ताकि पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं मीडिया के बीच समन्वय स्थापित करना उनकी प्रमुखता रहेगी और सूचना विभाग में बेहतर करने का प्रयास करेगी। कहा कि जिले में हो रहे सकारात्मक कार्यों को भी मीडिया कर्मी स्थान देते रहे, ताकि अन्य लोग भी प्रोत्साहित होते रहे। इस मौके पर प्रेस क्लब के महासचिव गोविंद पुंडीर, पूर्व अध्यक्ष गंगादत्त थपलियाल, जयप्रकाश पांडेय, मुकेश रतूड़ी, मधुसूदन बहुगुणा, रजत प्रताप सिंह, विजयदास, मुनेंद्र नेगी, अरविंद नौटियाल, जोत सिंह बगियाल, विजयपाल राणा, ज्योति डोभाल, धनपाल गुनसोला, रोशन थपलियाल, धीरेंद्र सकलानी आदि मौजूद थे।

सीएम पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर भाजपा ने फूंका कांग्रेस विधायक का पुतला

नई टिहरी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक पर विधायक मदन बिष्ट का पुतला फूंका।

पर सरकार और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंका। कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती है। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल कहा कि मदन बिष्ट चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसे में उन्हें शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी कर विधानसभा सत्र में अच्छा आचरण नहीं किया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर जिला महामंत्री राजेंद्र जुयाल, मंडल अध्यक्ष गोपीराम चमोली, देवेंद्र बेलवाल, शीशराम थपलियाल, राम लाल नौटियाल, जयेंद्र पंवार, राजेश डिंयूडी, हीरा नेगी, सभासद विनीत उनियाल, मानवेंद्र रावत, सतवीर नेगी, तौफिक अहमद, अब्दुल अतीक, असगर अली, सोहन चौहान, मदन चौहान आदि मौजूद थे।

श्रमिकों के कानूनी अधिकारों की जानकारी को चलेगा अभियान

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शचि शर्मा के निर्देशन में जनपद अल्मोड़ा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शविश्व सामाजिक न्याय दिवसश के उपलक्ष्य में आगामी 20 से 26 फरवरी तक विशेष अभियान शहक की बातश चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवाएं नालसा योजना 2015 के आलोक में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को मुफ्त कानूनी सहायता, लोक अदालत के लाभ, डिजिटल गिरफ्तारी/साइबर अपराध, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, यातायात नियम और नालसा के टोल फ्री नंबर (15100) आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

भाजपा सरकार का कांग्रेसियों ने फूंका पुतला

श्रीनगर गढ़वाल। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गोला पार्क श्रीनगर में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। बुधवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज घिल्डियाल,पूर्व पीसीसी सदस्य बीरेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र चौहान,नगर निगम पार्षद सूरज नेगी, रश्मि, राजकुमार और कुसुमलता ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को लूटने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है। महंगाई के दौर में पहले ही आम जनता आर्थिकी से जूझ रही है। ऊपर से सरकार स्मार्ट मीटर के नाम से प्रदेश की जनता को गुमराह कर जेब काटने का काम कर रही है। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप को महत्व दिए जाने पर प्रदेश की संस्कृति को गर्त में ले जाने की बात कही। बताया कि हमारा देवभूमि पौराणिक संस्कृति और विरासत का प्रतीक रही है ऐसे में लिव इन रिलेशन की खुली इजाजत देना प्रदेश के भीतर गलत माहौल को बढ़ावा देने जैसा है। कहा कि सरकार समय पर न जागी तो कांग्रेस यूसीसी कानून और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जाने का प्रदेश स्तर पर विरोध करेगी। मौके पर मीना रावत, आंचल राणा, बलवीर दानू, शिवकांत कंडारी आदि मौजूद रहे।

फार्मा एवं लैब एक्सपो आज से मल्टीनेशनल कंपनियां भी ले रही भाग

हरिद्वार। फार्मा एवं लैब एक्सपो की ओर से आज से होने जा रही तीन दिवसीय कार्यशाला में मल्टीनेशनल कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। विकास भवन रोशनाबाद में पत्रकार वार्ता में एसएमएयू इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड चौंबर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र गर्ग ने कहा कि विदेशों ने भी माना है कि भारत की दवाइयों में अच्छी गुणवत्ता है। भारत से विदेशी कंपनियां दवाइयां खरीद रही हैं। उत्तराखंड में फार्मा, कॉस्मेटिक और हर्बल इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को सरकार से और सरकार को उद्योगों से लाभ मिलेगा। कहा कि उत्तराखंड ग्रीन स्टेट है। यहां फार्मा एवं लैब एक्सपो की अपनी अलग पहचान है। कहा कि चौथी बार होने जा रहे एक्सपो में देश की 120

से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। साथ ही करीब 15 कंपनियां विदेशी कंपनियां भी अपने स्टॉल लगाएंगी।

रुद्रप्रयाग में तीन नाबालिग बालिकाओं के विवाह रोके

रुद्रप्रयाग। जिले के अनेक क्षेत्रों में बाल विवाह की सूचना मिलते ही वन स्टॉप सेंटर की टीम मौके पर जाकर परिजनों को मनाते हुए बाल विवाह को रोक रही है। बुधवार को भी अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी पर वन स्टॉप सेंटर की टीम ने जलई ग्राम सभा में 3 नाबालिग बालिकाओं का विवाह रोका। अब तक जनपद में कुल 10 बाल विवाह होने से रोके गए हैं। बुधवार को जलई में 3 नाबालिग बालिकाओं के विवाह की सूचना मिलने पर वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, बाल संरक्षण अधिकारी रोशनी रावत एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर अखिलेश सिंह मौके पर पहुंची।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आफॅसेट प्रिंटर्स 64 नेशविला रोड़ देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेन्ट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादकः
गार्गी मिश्रा
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।